

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2003—कार्तिक 16, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/एक/2.—श्री विवेक कुमार देवांगन, भा. प्र. से. (एम. टी.-93), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-02-13/2001/1-8.—श्री गिरीशचन्द्र बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही हैं, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2212/1767/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायगढ़ (छ. ग.) को दिनांक 19-9-2003 से 27-9-2003 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 28-9-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री सुबोध कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुबोध कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।
5. श्री सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायगढ़ के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री के. आर. पिस्टा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे।

रायपुर दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2214/1758/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मंडल, छ. ग. बिलासपुर को दिनांक 6-10-2003 से 10-10-2003 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 11-10-2003 एवं 12-10-2003 तक का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मंडल, छ. ग. बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री नारायण सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नारायण सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2221/1744/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. को दिनांक 4-9-2003 से 12-9-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 13-9-2003 एवं 14-9-2003 तक का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश काल में श्री शिवराज सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवराज सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 15-1/दो/गृह/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का गठन नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ शासन मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के वित्तीय आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन दिनांक 1-6-2001 की स्थिति में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच 76 : 25 एवं 23 : 75 के अनुपात से करने हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को अधिकृत करती है।

Raipur, the 20th October 2003

No. F 15-1/2 (Home)/2003.—In the event of non formation of Chhattisgarh State Police Housing Corporation in Chhattisgarh State, the State Government of Chhattisgarh hereby authorised Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation to divide financial liabilities and responsibilities of the Madhya Pradesh Police Housing Corporation as on 1-6-2001, in the ratio of 76 : 25 and 23 : 75 between Madhya Pradesh and Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

**गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)**

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-9-61/गृह/दो/03.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 एवं 23 जुलाई, 2003 को प्रश्नपत्र “प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया” प्रथम प्रश्नपत्र-भाग-बी, सी एवं द्वितीय, तृतीय प्रश्नपत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**निम्नस्तर
कलेक्टर रायपुर**

1. श्री शरदचंद यादव राजस्व निरीक्षक

कलेक्टर बिलासपुर

2. श्री वेदराम चतुर्वेदी राजस्व निरीक्षक

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	प्रश्नपत्र	स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कलेक्टर-रायपुर

1. श्री कमलप्रीत सिंह सहायक प्रथम उच्चस्तर
कलेक्टर एवं
तृतीय
2. श्री नारायण साहू राजस्व प्रथम उच्चस्तर
निरीक्षक एवं
तृतीय में निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

3. श्री भूषणलाल साहू राजस्व तृतीय निम्नस्तर
निरीक्षक

कलेक्टर-बिलासपुर

4. श्री प्रेमदोस मिरे नायब प्रथम निम्नस्तर
तहसीलदार
5. श्री रोहित यादव सहायक तृतीय उच्चस्तर
कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 8-6/2003/11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पश्चिम) के बायलर क्र. एम.पी./3656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30-9-2003 से दिनांक 30-11-2003 तक के लिये 2 माह की छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, विशेष सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4834/373/सी.एम./ज.सं.वि./2003.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (सिविल) को मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतनमान रुपये 16400-450-20000 में पदोन्नति प्रदान करते हुए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है :—

स.क्र.	अधीक्षण अभियंता का नाम, पद व वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त जहां पदस्थ किया जाना है, स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस. के. सरकार, अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन) कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर.	मुख्य अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना बिलासपुर (रिक्त पद पर).
2.	श्री अनूप सिंह चौहान, अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन) कार्या. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर.	मुख्य अभियंता (मानि-टरिंग), कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर.

2. श्री एस. के. सरकार, राज्य विभाजन फलस्वरूप म. प्र. राज्य को आवंटित है एवं परस्पर अदला-बदली के संबंध में आवेदन विचाराधीन है. यदि श्री सरकार का अदला-बदली प्रकरण अस्वीकार होता है एवं उन्हें म. प्र. जाना पड़े, तो छ. ग. राज्य में दी गई उक्त पदोन्नति म. प्र. में लागू नहीं होगी तथा श्री सरकार म. प्र. में नियमानुसार वरिष्ठता क्रम प्राप्त करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2069/807/आपर्या/2003.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य शासन एतद्वारा तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ नगर जामुल (भिलाई) का अभिन्यास स्वीकृत कराया गया था. उक्त स्वीकृत अभिन्यास की स्लाईस दो कुल रकबा 13729.5 वर्गमीटर के क्षेत्र में बाम्बे अम्बेडकर आवासीय योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के स्लाईस दो के भाग को छूट प्रदान करती है.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2072/1537/32/03.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 "क" की उपधारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जगदलपुर विकास योजना में उपान्तरण प्रस्ताव हेतु आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जगदलपुर के दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी. प्रकाशित सूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए.

अतः राज्य शासन एतद्वारा जगदलपुर की नजूल शीट क्रमांक 92, भूखण्ड क्रमांक 149/2, 149/5, 150, 157 एवं 152 कुल रकबा 1766.38 वर्गमीटर जगदलपुर विकास योजना में सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें के भू-उपयोग से वाणिज्यिक (पालिका बाजार) हेतु उपान्तरण की पुष्टि करती है तथा सूचना देती है कि उक्त उपान्तरण जगदलपुर विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2003

क्रमांक 148 एफ-73-160/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "ए सी एन यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा।

2. राज्य शासन एतद्वारा "ए सी एन यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो।

Raipur, the 24th October 2003

No. 148 F-73-160/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "A C N UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "A C N UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2003

क्रमांक 150 एफ-73-162/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा।

2. राज्य शासन एतद्वारा "दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो।

Raipur, the 24th October 2003

No. 150 F-73-162/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "DOON INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "DOON INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 सितम्बर 2003

क्रमांक 1615/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भेड़ी प.ह.नं. 13	6.04	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही कितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 सितम्बर 2003

क्रमांक 1615/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	शिकारीटोला प.ह.नं. 18	6.00	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही कितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 सितम्बर 2003

क्रमांक 1615/ले. प./भू-अर्वन/2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्वन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	गखईनडीह प.ह.नं. 19	6.49	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 सितम्बर 2003

क्रमांक 1615/ले. प./भू-अर्वन/2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्वन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	डोंगरापाट प.ह.नं. 19	13.61	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 सितम्बर 2003

क्रमांक 1615/ले. पा./भू-अर्जन/2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	घीना प.ह.नं. 19	19.43	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अति. सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5030/भू-अर्जन/2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	खैरबना प.ह.नं. 71/10	95.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खैरबना जलाशय के बांध पार राजनांदगांव.	एवं डूबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 243/क भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 2000-2001.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	भैंसा	0.04	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग,	जमुनैया नाला सेतु के पहुंच
				सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	मार्ग निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 244/क भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	करही	1.318	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग,	शिवनाथ नदी पर सेतु के पहुंच
				सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 23/अ-82/2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जेठूकांपा	2.28	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 26/अ-82/2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जेठूकांपा	1.92	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 27/अ-82/2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भठली	11.30	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 28/अ-82/2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पीड़ा	0.45	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक 851/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	मुडियाडीह प. ह. नं. 126/73	0.43	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	सोरमसिंधी जलाशय के माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

क्रमांक 893/अ.वि.अ./भू-अर्जन/46 अ/82/2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	गुलझर प. ह. नं. 110	1.31	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	कोटरीपानी जलाशय क्र. 1 के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

रा. प्र. क्र. 63/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार प. ह. नं. 15	0.837	कार्यपालन यंत्री/सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी सक्ती, जिला-जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी	2.756	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरवानी	2.960	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	टर्न की पद्धति से सिंधरा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लिटाईपाली	2.163	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	टर्न की पद्धति से धुरकोट उप वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2003-2004.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नवापारा	0.886	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

खसरा नम्बर
(1)

636/1

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

0.073

योग

1

0.073

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2002-03.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तुसेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 140/अ-82/2002-03.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		96/3	0.053
(क) जिला-रायगढ़		97/3	0.016
(ख) तहसील-खरसिया		139/2	0.085
(ग) नगर/ग्राम-रानी सागर		151/1, 150, 151/2, 152/1 1	0.028
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.662 हेक्टेयर		152/2	
		98	0.101
		81/1 ड	0.020
		85/1	0.020
		83/2	0.069
		88/3	0.065
		92/20	0.008
		89/1	0.162
		92/3	0.101
		81/12	0.008
		84/2	0.101
		81/11	0.105
		144/2, 146	0.364
		156/4	0.053
		101/3	0.045
		97/1	0.020
		96/1	0.040
		99/1	0.061
		81/16	0.142
		86/10	0.057
		86/6	0.081
		88/4	0.040
		90/2	0.121
		90/4	0.089
योग		66	6.662
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
81/15	0.081		
29/1	0.117		
145	0.085		
150, 151/1, 151/2 3	0.283		
152/1,			
152/2			
155/1	0.166		
156/3	0.332		
101/2	0.121		
100/1	0.101		
97/2	0.024		
81/13	0.008		
96/2	0.077		
84/1	0.259		
91/2	0.065		
86/9	0.032		
99/2	0.049		
155/2	0.008		
30/2	0.028		
31/1	0.206		
32/1	0.016		
33	0.243		
34	0.085		
35/5	0.113		
28/5	0.061		
35/2	0.125		
35/6	0.020		
134/1	0.243		
134/2	0.129		
135/1, 132, 133	0.093		
136/1, 136/2 2	0.247		
140	0.125		
138	0.057		
139/1	0.227		
142/2	0.109		
156/2	0.008		
159	0.032		
86/5	0.041		
156/5	0.008		
151/1, 150, 151/2, 152/1, 152/2 2	0.425		
101/4	0.158		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 146/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1)

(2)

(1) भूमि का वर्णन-		203, 204	0.300
(क) जिला-रायगढ़		220/2	0.016
(ख) तहसील-खरसिया		221	0.194
(ग) नगर/ग्राम-बसनाझर		164/2, 173	0.162
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.248 हेक्टेयर		310/757/2	0.028
		150/1	0.174
		151	0.235
खसरा नम्बर	रकबा	205, 206/3	0.207
(1)	(हेक्टेयर में)	224/1	0.283
	(2)	626	0.097
353/1	0.105	634	0.016
353/2	0.150	177/1	0.004
351/2	0.194	205, 206/4	0.190
352/2 ख	0.073	214/2	0.024
359/2	0.020	205, 206/2	0.004
351/1	0.121	224/2	0.008
352/2 क	0.020	214/3	0.008
359/1	0.008	222	0.069
349/2	0.231	214/4	0.004
329/1, 330/1। 3	0.020	153	0.101
329/1, 330/1। 4	0.125	152	0.073
329/1, 330/1, 334/2। 6	0.097	147/3, 248/2	0.061
329/2, 330/2	0.131	147/4, 148/3	0.085
337	0.134	145, 146	0.130
329/1, 330/1, 334/1	0.081	147/2, 148/1	0.069
579/1	0.004	635	0.004
336/1	0.065	117	0.211
336/2	0.049	579/3	0.061
108/6	0.077	579/2	0.061
329/1, 330/1, 334/3। 7	0.024	579/4	0.113
326/2	0.008	579/6	0.077
327/1	0.105	108/5	0.154
321	0.101	575/2	0.081
313	0.101	628	0.065
109	0.040	633/2	0.097
314/1	0.109	575/1	0.162
154/1	0.049	606	0.158
154/4	0.028	349/4	0.069
155/14	0.089	607/1	0.186
314/2	0.045	630	0.036
154/3	0.049	627	0.126
320	0.004	607/3	0.113
201	0.008		
314/3	0.024		
311/1	0.008		
315/1	0.138		
310/1	0.170		
310/2	0.166		

(1)	(2)
607/2	0.198
611	0.105
612/1, 612/2	0.004
612/4	0.105
615	0.263
625/1	0.097
625/2	0.036
631/2, 632/2, 633/2	0.049
631/6, 632/6, 633/6	0.036
645/2	0.040
631/1, 632/1, 633/1	0.081
631/5, 632/5, 633/5	0.073
631/4, 632/4, 633/4	0.053
155/12	0.032
580/1, 584/2	0.008
612/3	0.077
578/1	0.113
580/2	0.004
349/5	0.340
349/6	0.040
577	0.130
631/3, 632/3, 633/2	0.069
643/2, 639/2	0.008
योग	103 9.248

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

क्रमांक 876/भू-अर्जन/अ.वि.अ./12 अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-मुस्की, प. ह. नं. 141/88
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
245	0.10
328	0.13
योग	2 0.23

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

क्रमांक 877/भू-अर्जन/अ.वि.अ./42 अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-भलेसर, प. ह. नं. 143
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1617	0.10
1615	0.10
1619	0.02
1620	0.19
1625	0.06
1577	0.36
1622	0.12
1592	0.03
1591	0.04
1588	0.09
1590	0.10
1580	0.04
1581	0.14
1557	0.01
1538	0.32
1539	0.01
योग	1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भलेसर
व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

क्रमांक 888/भू-अर्जन/अ.वि.अ./27 अ/82/ सन् 2002-
2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे
दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-कलमीदादर, प. ह. नं. 122
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655	0.02
663	0.02
666	0.02
667	0.03
793	0.01
792	0.01
791	0.01
802	0.02
803	0.03
809	0.06
810	0.01
योग	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दाब-
पाली जलाशय के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

क्रमांक 889/भू-अर्जन/अ.वि.अ./43 अ/82/ सन् 2002-
2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे
दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1)

(2)

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-शेर, प. ह. नं. 131

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2069 0.07

2070 0.08

2072 0.04

2053 0.01

2073 0.10

2071 0.06

2068 0.01

2055 0.02

2014 0.05

2012 0.04

2065 0.03

2013 0.05

2085 0.03

2052 0.02

2054 0.03

2056 0.10

2057 0.03

2064 0.10

2043 0.06

2044 0.02

2042 0.04

2041 0.27

2040 0.07

1317 0.01

1312 0.01

1310 0.02

2011 0.01

2084 0.01

1367 0.04

1338 0.03

1368 0.02

1370 0.09

1363 0.03

1371

1372

1373

1365

1364

1366

1345

1344

1340

1337

1297

1335

1323

1298

1295

1294

1343

1321

1322

1292/2

1341

1316

1291

1314

1311

1296

1318

1319

1292/1

1315

1309

1293

योग

3.65

3.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भलेसर
व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण हेतु(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है

महासमुन्द, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

महासमुन्द, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

क्रमांक 890/भू-अर्जन/अ.वि.अ./11 अ/82/ सन् 2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-बरोण्डा बजार, प. ह. नं. 145
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
638	0.07
639	0.02
636	0.07
637	0.06
653	0.04
641	0.01
649	0.17
650	0.03
651	0.03
652	0.06
626	0.01
623	0.03
648	0.01
योग	13 0.61

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-बाघामुड़ा, प. ह. नं. 105/52
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
443	0.17
444	0.04
441	0.23
440	0.78
439	0.34
418	0.12
419	0.71
417	0.38
420	0.28
योग	9 3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कोडार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देवरी जलाशय अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

क्रमांक 892/भू-अर्जन/अ.वि.अ./13 अ/82/ सन् 2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)

(2)

573

0.26

548

0.26

योग

2

0.52

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खड़सा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पीढ़ी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

